(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सचिव/मंत्री कैप्टन जयपाल सिंह ने घोषणा की है कि 1 अक्तूबर, 1986 से नयी समिति बनायी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1986 के "भास्कर" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दुर्ग जिले के राजस्व अधिकारियों ने यह आरोप लगाया था कि उक्त समिति में ब्लैक मेल करने वाले लोगों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या 18 सितम्बर, 1986 को दुर्ग पुलिस स्टेशन में एक एफ० आई० आर० दर्ज करायी गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) राज्य सरकारों को खंड, जिला और मुख्यालय स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम प्रबोधन समितियां बनाने की सलाह दी गई है और इन समितियों में अन्य बातों के साथ-साथ संसद सदस्य, राज्य विधायक, उनके पार्टी संबंध को ध्यान में न रखते हुए अल्पसंख्यक समुदाय सहित गैर-सरकारी जन-प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हो सकते हैं ।

(ख) जी हां, मध्य प्रदेश के 20-सूत्री कार्यान्वयन राज्य मंत्री, कैप्टन जयपाल सिंह, ने कई पत्रकारों से अनौपचारिक विचार विमर्श किया और बताया कि जिला और खंड स्तर की समितियां 1 अक्तूबर, 1986 से पुनर्गठित की जायेंगी ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

(घ) से (च) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इन सूत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं है । राज्य सरकार से सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है ।

जनसाधारण के लिए जनता टेलिविजन सेट

2349. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसाधारण को रंगीन जनता टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या ऐसे टेलीविजन सेट उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस टेलीविजन का नाम क्या है और उसका मूल्य कितना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) जनता टाइप का रंगीन दूरदर्शन सेट एक ऐसे प्रयोजन मूलक रंगीन दूरदर्शन सेट को माना जा सकता है, जिसमें केवल न्यूनतम आवश्यक विशिष्टताएं हों और उसमें कोई अतिरिक्त विशिष्टताएं न जोड़ी गई हों ।

इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाला इलक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनालाजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई०टी०एण्ड०टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम अपने "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम०टी०बी०)" कार्यक्रम के अन्तर्गत वाजिब कीमतों पर इस किस्म के रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन करने के लिए उद्योग को आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ-साथ थोक मात्रा में सामग्री खरीदकर तथा उसकी आपूर्ति करके उनकी सहायता करता है ।

इस रंगीन दूरदर्शन का खुदरा मूल्य 6050 रु० है (जिसमें 1500/- रु० उत्पादन शुल्क तथा प्रसारण रिसीवर लाइसेंस फीस के एवज में 100/- रु० का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क शामिल है) लेकिन इसके साथ स्थानीय कर और वैद्युत यांत्रिकीय (इलेक्ट्रोमैकेनिक्स) ट्यूनर तथा ए०एफ०टी० अलग से लगेंगे । यदि सेट में इलेक्ट्रानिक्स ट्यूनर है तो उसका खुदरा मूल्य 6400/- रु० होगा ।

Commissioning for Ordnance Factory at Medak

2350. SHRI PUTTAPAGA RADHA-KRISHNA; Will the PRIME MINISTER bo pleased to refer to answer to Unstarred Question 1509 given in the Rajya Sabha on the 7th August, 1986 and state what progress has been made in commissioning of the proposed Ordnance Factory at Medak and by when it is likely to be commissioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRO-DUCTION AND SUPPLIES, IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL); The implementation of the Ordnance Factory Project at Medak is by and large progressing according to the schedules drawn up in consultation with the collaborators. The project is expected to be commissioned according to the planned programme.

It would not be in the national interest to disclos© further details.

Officers of Central Government and Ws undertakings on deputation

2351. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of officers of Central Government and its undertakings and corporations who are on deputation;

(b) the number of officers out of them who are on deputation from their Parent organisations for more than three years;

(c) the manner in which the parent , organisation manage the work in spite of the vacancies of such officers; and

(d) whether Government propose to ban deputations and create a separate pool specifically to fill up the vacancies in different departments and organisations, other-wise filled in by deputations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRJ BIREN SINGH ENGTI): (a) and (b) This information is not centrally monitored.

(c) When officers are released on depu^ tation, the parent Departments manage the work by local arrangements including through promotions, where necessary.

(d) There is no such proposal under consideration of the Government.

Nepalis deported front Meghalaya

2352. SHRI LAL K. ADVANI;
SHRI PRAMOD MAHAJAN;
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
SHRI SHANKER SINH VAGHELA;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) number of Nepalis rounded-up this year in Meghalaya and later deported to Nepal;

(b) how many of them were Indian citizens of Nepali origin; and

(c) what is the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI); (a) Between February 26 to March 4, 1986, 1056 Nepalis who were not in possession of Restricted Areas Permits were detected and sent across the border.

(b) According to the State Government of Meghalaya, care was taken to